सामुदायिक स्नानघरों/शौचालयों जैसे छोटे-मोटे निर्माण की बुनियादी भौतिक सुविधाएं देने का प्रस्ताव है, जिनका खर्च 60:40 के अनुपात में केन्द्र व राज्य सरकारों को देना होगा।

— आवास निर्माण और आश्रय सुधार की मौजूदा स्कीम 25 प्रतिशत की सब्सिडी (जो प्रति यूनिट 2500/- रुपये तक सीमित होगी) के साथ चलाई जाएगी। इस स्कीम में 10,000 रुपये तक के कर्ज का हुडको या किसी अन्य वित्तीय संस्था से लेने का प्रावधान है।

— राज्य/संघ राज्यों के बीच धन का आबंटन शहरी गरीबी के निपात और कस्बों की संख्या के संदर्भ में किया जाएगा।

— सामुदायिक गतिविधियों के लिए पहले साल 100/- रुपये प्रति व्यक्ति लागत और परवर्ती वर्षों में 75 रु० प्रति व्यक्ति लागत होगी।

— इस कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी तथा सामुदायिक विकास के उद्देश्य से उन्हें पूर्ण सहयोग देने का प्रावधान है।

— इन कस्बों में नेहरू रोजगार योजना तथा शहरी गरीबों हेतु बुनियादी सेवा स्कीम के शहरी गरीबी उपशमन के मौजूदा कार्यक्रम के तहत् सुलभ संसाधन, दोहरी राशि प्रावधान से बचने के लिए, अन्य कस्बों को अन्तरित किए जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) सवाल नहीं उठता।

(ङ) और (च) समूची पंचवर्षीय कार्यक्रम अवधि (1995-96 से 1999-2000) के लिए करीब 50 लाख (5 मिलियन) गरीबों की भलाई हेतु, केन्द्रीय हिस्से में 800 करोड़ रुपये का प्रावधान होगा। चालू वित्त वर्ष यानी 1995-96 में इस कार्यक्रम को चलाने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य

*73. **श्री ईश दत्त यादव:**
चौधरी हरमोहन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में स्थापित किए गए जन-स्वास्थ्य केन्द्रों से ग्रामीण जनसंख्या भी लाभान्वित हो रही है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री ए० आर० अन्तुले): (क) से (ग) ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। स्वास्थ्य स्थिति के आंकड़ों से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी के स्वास्थ्य में गिरावट आने का संकेत नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 50.6 वर्ष (1976-80) से बढ़कर 56.1 वर्ष (1986—90) हो गई है।

(घ) से (च) ग्रामीण जनसंख्या को उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से चिकित्सीय और परिवार।

Self Lease of Houses

*74. SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA:
SHRI ANANTRAM JAISWAL:

Will the Minister of URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to allow self-lease of houses;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken to solve huge arrears in allotment of houses to Government employees?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI R.K. DHAWAN): (a) No such proposal is under consideration of the Government.

(b) Does not arise.

(c) The construction of residential accommodation under the Central Government Employees' Housing Scheme is being augmented in different centres and particularly in Delhi. In addition to taking up such construction through direct budgetary allocation, certain schemes are also implemented by using land as a resource through agencies such as HUDCO with a view to increasing the availability of housing stock.

Posts Vacant in Public Enterprises Selection Board

*75. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH:
SHRI NAGMANI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of Chairman and Members in Public Enterprises Selection Board are lying vacant since 1st November, 1993;

(b) if so, the reasons for not filling up these vacancies; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir. The posts of Chairman and one Member have been lying vacant.

(b) and (c) The proposals for filling up the two posts are presently under active consideration of the Government.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मांगे

*76. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश भारतीय प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन ने यह मांग की है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को निलम्बित करने का अधिकार राज्य सरकारों से ले लिया जाए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों को निलम्बित किया है; और

(ग) भारत सरकार का इस संबंध में क्या विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1993 से 1995 (अब तक) की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के 29 अधिकारियों को विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा निलम्बित किया गया।

(ग) जब तक निलम्बन के आदेश जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी; भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण करते हैं, तब तक निलम्बन वैध माना जाता है।

Adverse Press reports on Defence Equipments

*77. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have seen adverse Press reports about the capability of the Arjun as the Main Battle Tank, the suitability of the Kaveri engines for our Light Combat Aircraft and the quality of our Advanced Light Helicopter;

(b) whether it is a fact that these reports are planted by our rivals in the world arms market; and

(c) what steps Government propose to take to stop these anti-national reports?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPTT. OF DEFENCE RESEARCH AND